विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित डा० मान सिंह यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
2 (क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि किये जाने हेतु सरकार के पास कोई कार्य योजना है ?	सरकार ने किसानों के लिए उच्च आय प्राप्त करने की दृष्टि से कई विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया है। आय वृद्धि की सम्भावनाओं का संदोहन करने के लिए कई सुधार किये है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम है, जो निम्नवत् है :- 1. खेती के साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य आदि की समन्वित व्यवसायिक खेती पर बल। 2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। 3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान भाइयों को खाद-बीज के लिए आवश्यक व्यवस्था हो सके, इसके लिए प्रति चार माह पर रू० दो हजार की धनराशि का उनके खातों में अन्तरण कराना। 4. किसानों के उत्पादन को एम.एस.पी. के आधार पर समय से खरीद और भुगतान की व्यवस्था। 5. प्रधानमंत्री कृषि संरचना (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड) से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण, भण्डारण और मूल्य वर्धन के लिए प्रयास। 6. प्रदेश में पैक्स हाउसों का निर्माण कर फलों व सब्जियों के निर्यात की व्यवस्था। 7. प्रदेश के रेनफेड क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विस्तार। 8. पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियो पर प्रभावी नियंत्रण से उत्पादन वृद्वि। 9. खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग हेतु आधारित अवस्थापनाओं में निजी उद्यमियों की सहभागिता) 10. किसान के उत्पाद के उचित मूल्य प्राप्ति हेतु विपणन की व्यवस्था सुलभ कराना। 11. फसल बीमा के अन्तर्गत अधिक से अधिक कृषकों को आच्छादित करना एवं उन्हें बीमा का लाभ उपलबध कराना। 12. कृषि विविधीकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन।

	13. किसान पाठशाला, गोष्ठियो और मेले के द्वारा किसानों को जागरूक करना। उक्त के अतिरिक्त किसानों के लिए उच्च आय प्राप्त करने तथा आय वृद्धि हेतु आत्म निर्भर पैकेज (कृषि) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के साथ एफपीओ का गठन और संवर्धन, कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से अवसंरचना निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अन्तर्गत फसल बीमा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सिंचाई की बेहतर पहुंच, कृषकों हेतु लाभ मार्जिन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना, कृषि यंत्रों तथा उन्नत किस्म के आधुनिक बीजों पर अनुदान की व्यवस्था, ब्याज सबवेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जैविक खेती को बढ़ावा देना, कस्टम हायरिंग सेंटर तथा फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना, नवीन तकनीकी सिखाने हेतु सभी मुख्य फसलों का फसल प्रदर्शन, सोलर पम्पों की स्थानपा हेतु अनुदान की व्यवस्था तथा प्राकृतिक खेती इत्यादि कार्यक्रमों/ योजनाओं/नीतियों द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे है।
(ख) यदि हॉ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता है।

सूर्य प्रताप शाही
कृषि मंत्री।